in the Indian Copyright Act I am willing to examine that matter and come to Parliament with a proposed amendment

SHRI A P JAIN May I know whether any complaint has been made to the hon'ble Minister that as a result of India being a party to international agreements, that is, Paris Agreements etc, there are difficulties in publishing the text of all foreign books in India and, therefore, the Indian publishers are unable to publish the text of the foreign books with the result that the foreign books are very costly and people cannot avail of them in sufficiently large numbers ?

PROF S NURUL HASAN : Although this question is not directly connected with the question here, I am prepared to answer it This is a matter which has been brought to the notice of the Government of India and has been engaging our attention It is a question of balancing. If we are not a part of the various international conventions, then our films and records will not get the protection of international convention And as the House undoubtedly knows, Sir, a considerable amount of money of foreign exchange comes to the country because of these records and films and other forms So, both these matters are interconnected and a decision only on one aspect cannot be taken

दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए मकान

*620. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970–71, 1971–72 और 1972–73 के वर्षों के दौरान दिल्ली में किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकान बनाये गये हैं अथवा बनाने का विचार है, और

(ख) क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकान उनके कार्यालयों के समीप बनाने और ऐसे रिहायशी मकानों का प्रतिशत बढ़ाने का भी विचार रखती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

†[ACCOMMODATION FOR CLASS IV EMPLOYEES IN DELHI

*620 SHRI SURAJ PRASAD Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) the names of places in Delhi where residential houses have been constructed or are proposed to be constructed for Class IV employees of the Central Government during the years of 1970-71, 1971-72 and 1972-73; and

(b) whether Government propose to build residential houses for Class IV employees close to their offices and also to increase the percentage of such residential units and if not, what are the reasons therefor ?]

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (PROF DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA) (a) (1) DIZ area, New Delhi

(2) Thyagaraja Nagar.

(3) Masjid Moth

(4) Timarpur.

(5) Andrewsganj.

(b) It is the intention of Government to construct quarters for low-paid employees as near to their place of work as possible, subject to the availability of land. It is also Government's intention to increase the percentage of satisfaction for residential units of low paid employees.

‡**निर्माण और आवास मंत्री (प्रो० देबीप्रसाद चट्टोपाध्याय)** : (क) (1) डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली।

(2) त्यागराज नगर।

(3) मस्जिद मोठ।

(4) तिमार पुर।

(5) ऐंड्रूज गंज।

†[ ] English translation.

‡[ ] Hindi translation.

(ख) सरकार का विचार यह है कि भूमि उपलब्ध होने पर निम्न आय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण यथा सभव उनके कार्यस्थान के निकट किया जाए। सरकार का यह भी इरादा है कि निम्न आय के कर्मचारियों के रिहायशी मकानों की परितुष्टि की प्रतिशतता को बढ़ाया जाये।

श्री सूरज प्रसाद मत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे यह मालूम होता है कि जितनी भी जगहे इन्होंने बताई है, वह पार्लियामेट के इर्द-गिर्द नही है, बहुत दूर पडती है। ऐसी हालत मे मै सरकार मे यह जानना चाहूगा कि जो एक इफार्मेशन इसमे नही मिली कि 1970-71, 1971-72, 1972-73 मे इन्होंने कितने मकान बनाये इसको देने का कष्ट करे।

दूसरी बात यह कि क्या सरकार इस बात को बतायेगी कि चतुर्थ ग्रेड के जो एम्प्लाईज है, उनकी सख्या सेंट्रल गवर्नमेंट मे कितनी है और उनमे मे कितनों को सरकार ने अभी तक क्वार्टर प्रावाइड किये है?

PROF DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA. Sir as I have already said the provisions of quarters to the employees near the Parliament House or the Secretariat depends upon the availability of the land As you know, Sir, there is not much available land in these areas Within these constrains we are doing our best Secondly, about the Class IV employees number, I think it is a different question and we need notice for that But about the percentage of satisfaction. I can supply the information Regarding Type I quarters, the percentage of satisfaction is nearly 49 By the end of the Fourth Five Year Plan, we hope to raise it to 51 per cent And we have envisaged that by the end of the Fifth Five Year Plan, we will be providing quarters to 75 per cent of the Class IV employees.

श्री सूरज प्रसाद फिर यह फिगर्स नही मिली कि 1970-71, 1971-72 और 1972-73 मे कितने क्वार्टर्स बनाये। ये फिगर्स दी ही नही। यह फिगर दे दें कि कितने वहा बनाये। यह हमारे क्वेश्चन मे था, यह हमने उसी मे पूछा था, यह फिगर उन्होंने दी ही नही।

PROF DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA I shall give the number. In the DIZ Area we are constructing 64 houses, in Thyagaraja Nagar, 128 houses—these are Type I quarter—and in Masjid Moth 48 houses In the Andrewsganj area 64 houses are under construction In Irnarpur area 128 are under construction And in the DIZ area, New Delhi, 184 will be taken up shortly

श्री सूरज प्रसाद मेरा दूसरा सवाल है।

श्री सभापति आप तो कर चुके, आपने तो पूछ लिया।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव उन्होंने जवाब ही नही दिया था।

श्री सभापति आपने तो जवाब दे दिया अब आपको नही बुलायेंगे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव जवाब नही देते इसलिए तो तीन-तीन बार उठना पडता है।

श्री सूरज प्रसाद दूसरा सवाल मेरा यह है कि जिन जगहो का नाम इन्होंने बताया, वहा के लिये उन्होंने खुद स्वीकार किया कि पार्लियामेट से और सेक्रेटेरिएट से वे जगहे बहुत दूर है, तो ऐसी अवस्था मे जो सरकार के कर्मचारी है, जो फोर्थ ग्रेड के है, उन्हे बहुत दूर से सेक्रेटेरिएट मे आना पडता है और इससे उनको बहुत कठिनाई पडती है, तो क्या सरकार इस बात का विचार करने को तैयार है कि जब तक कि सेक्रेटेरिएट के इर्द-गिर्द उनको क्वार्टर्स नही दे देते, तब तक उनके परिवहन की व्यवस्था करे ताकि वे

आसानी से आ जा सकें। मै ट्रांस्पोर्ट अरेजमेंट करने के बारे मे पूछ रहा हू।

श्री उमाशंकर दीक्षित श्रीमन्, इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे विचाराधीन नही है।

श्री सूरज प्रसाद इस तरह की व्यवस्था तो प्राइवेट एम्प्लाइज के लिए भी लोग करते है कि जहा-जहा जिस-जिस जगह है, वहा मे लाने के लिये करते है।

SHRI MONORANJAN ROY I find that in three years, the Ministry has constructed 392 quarters for 392 employees. Now the pertinent question was about the total number of Class IV employees working in the Central Government in Delhi, and the Minister has replied that he cannot at the moment say what their number is It seems that this figure of 392 is not even 10 per cent of the total Class IV employees employed in the Central Government here. How many years will it take—the Minister only says "under construction", 'to be taken up shortly", "expected" and so on—to provide quarters to all the Central Government Class IV employees in Delhi?

PROF. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA Firstly, Sir, the number of the Class IV employees who have put forward demands for quarters is 26,735, and the number of employees who have been provided with quarters is 12,961. The percentage of satisfaction is 49.2 to be precise. But, Sir, the condition of persons eligible to quarters of Types II and III is worse than that of Class IV employees, because the percentage of satisfaction in regard to people who draw salaries between Rs. 175 and Rs. 349 is 26.2. So, Sir, the problem is not bad only for the Class IV employees It is worse for. . . .

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: सेटिसफेक्शन की व्याख्या क्या है?

श्री सभापति: उन्हे खत्म करने दीजिए।

PROF DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA We have already agreed and conceded that the satisfaction rate of the Class IV employees is slightly better than the others About the other question, I have already said that according to our plan, by the end of the Fifth Five-Year Plan, the percentage of satisfaction regarding accommodation to employees eligible to Types I, II, III and IV will be 75 per cent. When it will be cent per cent, I cannot say now.

SHRI KALYAN ROY: The Minister is very much satisfied with the percentages.

श्री लाल आडवाणी श्रीमन्, मत्री जी का यह कहना सही है कि क्लास फोर एम्पलाइज के लिए आवास की व्यवस्था करने की बात, निकट मे कोई भूमि उपलब्ध है या नही, इस पर निर्भर करेगा। तो क्या मत्री जी सदन को यह आश्वासन दे सकते है कि अभी जो पुराने मकान हो चुके है, जैसे गोल मार्केट की एरिया मे और मिन्टो रोड एरिया मे और जिनको बुल डाऊन करके वहा पर रिकन्सट्रक्शन हो रहा है, वहा प्रमुख रूप से क्लास फोर एम्पलाइज को ही आवास दिया जाएगा?

श्री उमाशंकर दीक्षित श्रीमन्, हमारी तो नीति यह है कि जहा जिस क्लास के लोग है, वहा प्राय उनके लिए ही व्यवस्था करना चाहेगे। कोई इस तरह का अतर करना कि क्लास 2 या 3 को हटा कर क्लास 4 या एक को लाए, ऐसा करना कठिन होगा। लेकिन यह जरूर है कि जहा पर वे पहले से है, वहा दूसरो को देने की जरूरत नही है, उच्च कक्षा वालों को।

श्री लाल आडवाणी: श्रीमन्, मैं समझता हू...

श्री सभापति अब आप बहस न करिए।

श्री लाल आडवाणी उसका कारण यह है—उनका कहना सही है कि वहा रहने वालों को आवास अवश्य दिया जाएगा, लेकिन वहा पर जो मल्टी स्टोरीज

की योजना है फोर्थ क्लास एम्प्लाइज के लिए ..

श्री सभापति : बस अब हो गया।

श्री लाल आडवाणी नहीं, वह जवाब दे रहे हैं।

MR. CHAIRMAN : Mr. Krishan Kant.

PROF. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : Sir, I just want to add one thing to the original question as to whether Class IV employees or for that reason Class III employees could be provided possibly in the near future with quarters nearer Parliament House or the Secretariat. It is perhaps pertinent to observe that we have a Redevelopment Authority of Delhi —we have appointed a Committee on Redevelopment of Delhi—which is particularly going into what we call bungalow areas adjacent to the Secretariat and Parliament House mainly consisting of the big Type VIII quarters in which Ministers and Secretaries are housed. Now there is a proposal of remodelling all these areas and we are not constructing any more Type VIII quarters when these buildings are dismantled and when the Redevelopment Plan is finalised we hope that somewhere near Parliament House and the Secretariat land will be available for the construction of multi storey buildings wherein perhaps Class IV and other low-paid employees could be provided with quarters.

SHRI KRISHAN KANT : May I know what the percentage is of Class I officers, Class II officers, Class III officers and Class IV officers, who are without Government accommodation ?

PROF. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : If I can answer the question slightly in a reverse way, I can say it this way. The percentage of dissatisfaction amongst persons entitled to Type VIII quarters is 12 per cent.

SHRI KALYAN ROY : Sir, what is this satisfaction or dissatisfaction ? I do not understand it.

SHRI GANESH LAL CHAUDHARY : What is the measurement of satisfaction ?

PROF. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : I am sorry the term satisfaction sounds slightly psychological. But the matter is very material. It means the percentage of the accommodation provided and not provided. . ..

SHRI KRISHAN KANT : Sir, let the Minister give us figures. I asked about Class I, Class II, Class III and Class IV.

PROF. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : I am sorry I was stopped, but I did not stop. I was telling that the percentage of dissatisfaction amongst persons who are entitled to Type VIII quarters but have not been provided with, is 12 per cent. Twelve per cent of the people who are eligible to Type VIII quarters have not got accommodation. Twenty-three per cent of the people entitled to Type VII quarters are without quarters. Twenty-five per cent of the people entitled to Type VI are without quarters. The percentage of dissatisfaction, with apologies to Mr. Roy, is not uniform and it is there even in the case of top people.

SHRI MONORANJAN ROY : Sir, on a point of order. The Minister's reply pertained to Type VIII quarters ...

MR. CHAIRMAN : This is no point of order.

SHRI MONORANJAN ROY : The question was about the percentage of Class IV, Class III, Class II and Class I officers. That was the question. But the Minister has evaded that very question.

MR CHAIRMAN : This is no point of order.

SHRI GANESH LAL MALI : There is a provision for construction of houses for Class IV employees of the Central Government, I would like to know from the hon. Minister whether a similar provision has been made for Class IV employees of the States in the Fifth Five Year Plan.

PROF. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : This question should perhaps be addressed to the State Governments. We are sorry we are not in a position to answer it.

श्री चक्रपाणि शुक्ल : क्या शासन को मालूम है कि बहुत से फर्स्ट क्लास और सेकेन्ड क्लास आफिसरों के खुद के यहा पर मकान है और फिर भी वे शासकीय मकानों पर रहते है ? तो क्या सरकार इस तरह के आफिसरों को अपने-अपने मकानों में रहने के लिए बाध्य करेगी ताकि दूसरे लोगों को जिन्हें मकान अभी तक नहीं दिये गये है, उन्हें दिये जा सकें ?

PROF. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA : This is a big policy matter. It was examined in the Ministry and it was decided that since buildings constructed by these officers are also being used by some other people, if they are forced to give up their quarters, the physical problem of shortage of accommodation will be there in the city as a whole.

SHRI KALYAN ROY : This is how you are carrying out your Garibi Hatao programme.

SHRI MONORANJAN ROY : They are getting Rs. 2,000 rent.

मंत्रियों के निवास स्थानों में परिवर्धन और परिवर्तन

***621. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री मान सिंह वर्मा :
श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा :
डा० भाई महावीर :
श्री रत्तन लाल जैन :
श्री ओइम् प्रकाश त्यागी :

क्या निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1969 से अब तक दिल्ली मे मंत्रियों के निवास-स्थानों में परिवर्तन तथा परिवर्धन और मरम्मत के कार्यों पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ख) इस अवधि में इन निवास-स्थानों को कुल कितने मूल्य का फर्नीचर बिजली का सामान तथा अन्य सामग्री सप्लाई की गयी ?

†[ADDITIONS AND ALTERATIONS IN THE RESIDENCES OF MINISTERS

*621. SHRI J. P. YADAV :
SHRI MAN SINGH VARMA :
SHRI V. K. SAKHLECHA :
DR. BHAI MAHAVIR :
SHRI RATTAN LAL JAIN :
SHRI O. P. TYAGI :

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on additional alterations and repairs to the Ministers' residences in Delhi from the 1st August, 1969 up-to-date; and

(b) The total value of furniture, electric appliances and other articles supplied at these residences during that period ?]

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT) : (a) Rs. 29,68,067.45.

(b) Rs. 7,83,776.18.

‡[**निर्माण और आवास मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित)** : (क) 29,68,067.45 रुपये ।

(ख) 7,83,776.18 रुपये ।]

SHRI MAHAVIR TYAGI : This is terrible. They should curtail the expenditure.

SHRI KALYAN ROY : What is this hotel expenditure ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन् यह आस्ट्रेरिटी का जो नमूना है, इसमें मैं यह बात जानना चाहता हूं कि राज्य मंत्री और उपमंत्रियों के ऊपर कितना खर्चा हुआ । क्या आप इस बारे में ब्रेक अप बतलायेंगे कि किस मंत्री के ऊपर अलग मे किस मद पर कितना-कितना मैक्सिमम खर्चा हुआ है ? इसी तरह से मंत्रियों, राज्य

†[ ] English translation.
‡[ ] Hindi translation.